



## नई ई-कॉमर्स नीतियों से बड़ी कंपनियों को झटका

### संपादकीय

एक फरवरी से लागू हुई नई ई-कॉमर्स नीति से जहां छोटी और घरेलू कंपनियों ने राहत की सांस ली है, वहीं बड़ी और विदेशी कंपनियों में अवसाद की स्थिति बन गई है। सरकार की नई नीति के अनुसार ई-कॉमर्स वाली कंपनियां अब अपने विक्रेता पर स्वामित्व नहीं दिखा सकेंगी और न ही इन्वेंटरी पर नियंत्रण कर सकेंगी। सरकार ने इन नीतियों का ऐलान इसलिए किया, ताकि छोटी-बड़ी सभी कंपनियों को व्यापार करने का समान अवसर मिल सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ई-कॉमर्स ने एक ओर भारत के फुटकर बाजार पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया था और दूसरी ओर भारत में ही उभर रही कंपनियों का अधिग्रहण भी चालू कर दिया था। एक तरह से वह स्थिति पैदा होने लगी थी, जिसकी आशंकाएं वैश्वीकरण के आरंभ में जताई जा रही थीं। पिछले साल वॉलमार्ट ने 77 प्रतिशत शेयर खरीदकर भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट पर कब्जा कर लिया था। इस बीच जिस तरह से उसके पुराने संस्थापकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर उन्हें निकालने की प्रक्रिया हुई, वह व्यावसायिक जगत के भीतर चलने वाली साजिशों की एक बानगी थी। इसलिए अब उन बड़ी कंपनियों पर दबाव बन रहा है, जो चाहती थीं कि सारा बाजार उनके कब्जे में आ जाए।

यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग कंपनियां धमकीभरी चेतावनी दे रही हैं कि जिस तरह वॉलमार्ट ने 2017 में चीन का बाजार छोड़ दिया, उसी तरह वह भारतीय बाजार भी छोड़ देगी। दावा किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन को मार्च 2018 तक 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगले तीन साल में यह नुकसान दो गुना हो जाएगा। अगर फ्लिपकार्ट को अपने 20 प्रतिशत उत्पाद मार्केट प्लेस से हटाने पड़ें तो राजस्व में 40 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। स्थिति तो यही है कि इस कंपनी को 25 प्रतिशत उत्पाद हटाना पड़ेंगे। इनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य का सामान है। इसके बावजूद सारा माहौल इतना नकारात्मक नहीं है, जितना बताया जा रहा है। वॉलमार्ट भारतीय बाजार के आकार को देखते हुए अभी भी आशावादी है। वह सोच रही है कि भले ही एफडीआई पर नए किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं लेकिन, भारत का बाजार बड़ा है। यहां अभी ग्रामीण क्षेत्र में ई-कॉमर्स का प्रवेश होना है। इस दौरान ई-कॉमर्स की गति भी तेज हो रही है। इसलिए ज्यादा निराश होने की स्थिति नहीं है।

**Date:07-02-19**

## नागरिकता बिल पर गतिरोध

### संपादकीय

यह ठीक नहीं कि तीन तलाक संबंधी विधेयक की तरह से नागरिकता संबंधी विधेयक पर भी पक्ष-विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसका बड़ा कारण विभिन्न दलों की ओर से अपने-अपने राजनीतिक हितों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया जाना है। चूंकि आम चुनाव करीब आ गए हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी हितों की चिंता करें, लेकिन इस कोशिश में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति का एक बड़ा आधार यह है कि आखिर इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय के लोगों को ही भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान क्यों है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर क्यों रखा गया है? सैद्धांतिक तौर पर यह आपत्ति उचित नजर आती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसका औचित्य नहीं नजर आता कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों को वैसी ही रियायत दी जाए जैसी इन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देने की व्यवस्था की गई है।

सभी को एक समान नजर से देखने की मांग करने वाले विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उक्त तीनों देशों से प्रताड़ित होकर भारत की राह देखने वाले मूलतः वहां के अल्पसंख्यक ही होते हैं, न कि बहुसंख्यक। वे इस तथ्य को भी ओझल नहीं कर सकते कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल और असम के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के तमाम इलाकों का सामाजिक संतुलन किस तरह गड़बड़ा गया है। आदर्शवादी सिद्धांत जमीनी हकीकत से मेल भी खाने चाहिए। यह कोई तर्क नहीं हुआ कि भारत दक्षिण एशिया का बड़ा देश है और उसे उन सभी को शरण देनी चाहिए जो इस देश में बसना चाहता है। भारत का संविधान भारत के लोगों पर लागू होता है, बाहर के नागरिकों पर नहीं और यह तय करना देश विशेष का अधिकार है कि वह किसे शरण दे और किसे नहीं?

आखिर विपक्षी दलों के साथ इस विधेयक का विरोध करने वाले अन्य लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि बाहरी लोगों की घुसपैठ और खासकर बांग्लादेशियों की अवैध बसाहट से असम की संस्कृति किस तरह खतरे में पड़ गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार हुआ उसका एक बड़ा मकसद असम की मूल संस्कृति को बचाना नहीं है? यह सही है कि असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में नागरिकता विधेयक का विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी वजह वह नहीं है जिसे विपक्षी दल बयान कर रहे हैं।

असम और अन्य राज्यों में इस विधेयक का विरोध तो इस आशंका के चलते हो रहा है कि अगर पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को उनके यहां बसा दिया गया तो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी? बेहतर हो कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के उन लोगों और समूहों की चिंताओं को दूर करे जो नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं। निःसंदेह उसे विपक्षी दलों से भी व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके। राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया जाए तो ऐसा हो सकता है।

## Writ In Snow

*Study on receding glaciers in Hindu Kush underlines need for cooperation between countries that share Himalayas.*

### Editorial

Success in meeting the Paris Climate Pact's most ambitious target might not be enough, a recent study says, to prevent a serious meltdown in the Hindu Kush Himalayas. Released on Monday, the Kathmandu-based International Centre for Integrated Mountain Development's (ICIMOD) "Hindu Kush Himalaya Assessment" reveals that more than 35 per cent of the glaciers in the region could retreat by 2100, even if the global temperature rise is capped at 1.5°C. This could destabilise the hydrology of large parts of South Asia, China and Myanmar.

Regions in higher altitudes tend to warm faster than low-lying lands. So, a global temperature increase of 1.5°C could mean at least a 1.8°C temperature rise in the Hindu Kush Himalayas, the ICIMOD study warns. This will have a major bearing on the ice-fields, which are the largest repository of permafrost outside the polar regions. The region's snow is the source of 10 major river systems — including the Ganga, Indus, Brahmaputra and Mekong — in India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, China and Myanmar. Large-scale warming could drastically alter the river flows in these countries. The receding glaciers could cause a deluge in

the rivers during the monsoon while the flows are likely to plummet during the dry seasons, with serious implications for irrigation, hydropower and ecosystem services.

Climate scientists have tried to link the Subcontinent's erratic monsoons over the past 10 years — days of intense rainfall combined with drought-like conditions — to global warming. They have, however, stopped short of identifying the exact causes of these extreme weather events. The ICIMOD study offers clues that the receding glaciers might be the reason for the changing monsoon. "The number of intense precipitation days and intensity of extreme precipitation have increased overall in the last five decades. If these trends persist, the frequency and magnitude of water-induced hazards in the (Hindu Kush Himalaya) region will increase," it says. This is a significant conclusion given that developments in the Himalayas are known to have a spin-off on the monsoon in the Subcontinent. The ICIMOD researchers point out that more studies are required to firm up the links between extreme weather events in the higher reaches of the Subcontinent and the erratic weather in the plains. For this, they advocate more data sharing between the countries that share the Hindu Kush Himalayas. Even more salient is their message that political differences between these countries should not come in the way of joint efforts to build resilience of vulnerable communities and shore up the region's water security. Such cooperation must go alongside meeting the Paris Climate Change Pact's goals.